कृषि संबंधी नीतियों और कार्यक्रमों के संबंध में उच्चाधिकार शक्ति प्राप्त समिति का प्रतिवेदन

596. डा० जिनेन्द्र कुमार जैन :
श्री राम जेठमलानी :

क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कृषि संबंधी नीतियों और कार्यक्रमों के संबंध में उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने हाल ही में सरकार को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है ;

(ख) क्या उक्त प्रतिवेदन में भारतीय खाद्य निगम के कार्यक्रम में परिवर्तन करने की सिफारिश की गई है ;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा कब और क्या निर्णय लिए जाने की संभावना है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम पूजन पटेल) : (क) से (घ) सरकार द्वारा फरवरी, 1990 में श्री भानु प्रताप सिंह की अध्यक्षता में गठित की गई सलाहकार समिति ने अभी तक अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है । समिति ने कुछ अंतरिम सुझाव दिए हैं। ये सुझाव कृषि मंत्रालय के विचाराधीन हैं ।

Selection of Incumbent for Appointment to the Post of Director General, ICAR

597. DR. JINENDRA KUMAR JAIN:
SHRI RAM JETHMALANI:

Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the terms of office of the former Director General of I.C.A.R. expired on the 31st March, 1990;

(b) whether it is a fact that process for the selection of the new incumbent for this post was started about six months back;

(c) whether it is also a fact that the selection committee has recommended some names for the appointment; and

(d) if so, what are the reasons for not making any appointment out of those recommended names and what steps have been taken by Government to speed up this work?

THE DEPUTY PRIME MINISTER AND THE MINISTER OF AGRICULTURE (SHRI DEVI LAL): (a) Yes Sir.

(b) A Search Committee for suggesting a panel of name for consideration by Govt. for appointment of Secretary, Department of Agricultural Research & Education, who also functions as Director General, Indian Council of Agricultural Research was constituted on 17.1.90.

(c) and (d) The Committee initially submitted a panel of names; but due to certain representations, the committee was asked to reconsider the matter and submit its recommendations. Meanwhile, Secretary, Department of Agriculture & Cooperation is holding the post as an additional charge.

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से मूल्य वृद्धि पर नियंत्रण

598. श्री राम नरेश यादव : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पिछले तीन महीनों के दौरान आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में हुई वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से कोई कदम उठाए हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है; और